phenomenon and a very undesirable trend which needs to be curbed forthwith. It appears that the matter is already within the knowledge of the authorities, but apparently there is an attitude of helplessness. It is understood that the matter is also within the knowledge of the honourable Minister for Works and Housing and he has also expressed his concern in this regard. A news item from the *Times of India* dated the 30th March, 1977 reads as under:

> "The Union Minister for Works and Housing, Mr. Sikandar Bakht, today expressed his concern about reports that a spate of encroachments on land had started taking place in Delhi. He wanted the authorities concerned to deal firmly with such encroachments and keep a constant vigil against any unauthorised occupation of land in future. However, he said that no strong arm methods are to be adopted in this regard. Mr. Sikandar Bakht was addressing senior officials of the Ministry and heads of the public sector undertakings."

Sir, from the news item it seems that the Minister is particular that no strong arm methods should be used for the vacation of unauthorised encroachments. We are not interested in the type of methods that are to be adopted to get the unauthorised encroachments vacated, but certainly we would like that these encroachments should not be there. What methods are adopted to prevent them, is not our concern. We feel that this matter should get more serious consideration. Otherwise, we do not think anything can be achieved by persuasion only. If we do not take immediate and appropriate action, I am sorry to say that at a later stage the dimensions of the problem will be so much that we will not be able to or the Government will not be able to do anything about it, and I hope that they will not allow these things to continue as they are being done now.

REFERENCE TO PROCUREMENT PRICE FOR WHEAT

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : कल भी मैंने आपके माध्यम से कृषि मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहा था कि गेहूं की फसल किसानों के घर में आ रही है। कई प्रदेश इस प्रकार के है जहां गेहूं कट चुका है और कई प्रदेश इस प्रकार के है जहां गेहूं इस समय कट रहा है। मैंने आपके माध्यम से यह जानना चाहा था कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में प्रदेशों के मुख्य मन्त्रियों की बैठक बुला रही है जिससे गेहूं का वसूली मूल्य निर्धारित हो सके ? क्या यह निर्णय इस चालू अधिवेशन में हो जाएगा ? क्योंकि अगर यह लूट फिर शुरू हो गई तो परिणाम यह होगा कि किसान बरबाद हो जायेंगे। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गेहूं की कीमत के सम्बन्ध में तो कई बार कहा गया है, दूसरे अनाजों के सम्बन्ध में भी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन में कुछ किसानों को शामिल किया जाए। बाबू लोगों पर किसानों का भाग्य नहीं छोड़ देना चाहिये। मै यह भी जानना चाहता हूं कि नये कृषि मन्त्री, जो कमीशन का ढांचा इस समय है क्या उसमें किसी तरह के परिवर्तन की बात सोच रहे है ? तीसरी बात जो मैं विशेष रूप से पूछना चाहता हूं कृषि मंत्री जी से, क्योंकि वह स्वयं एक किसान है और वह जानते हैं कि गेहूं की लागत मूल्य इस समय क्या है। सरकार ने जब एक नीति निर्धारित की हुई है कारखानों में जो उत्पादन होगा उस पर कारखाने वाले 10 प्रतिशत लाभ उठा सकते है तो जो सुविधाएं कारखाने वालों को दी हुई हैं वही सुविधाएं किसानों को देने के लिये सरकार क्यों चुप है ? मैं स्वयं एक किसान परिवार से आता हूं जहां तक मेरी जानकारी है इस समय जितने लगान बढ़ गए हैं, सिंचाई की दरें बढ़ गई है और दूसरे टैक्सेज बढ़ गए हैं इन सब को मिला कर किसानों को इस समय 125 रुपए लागत मूल्य बैठता है और अगर 10 परसेंट से लगाते हैं तो 137.50 पैसे

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

बैठते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कृषि मंत्री जी इस प्रकार का निर्णय लेने जा रहे हैं जिससे गेहूं की लूट फिर से शुरू न हो जाए। मैं रबी राय जी से नहीं पूछ रहा हूं मैं कृषि मंत्री जी से पूछ रहा हूं।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : जहां तक गेहूं की कीमत मुकर्रर करने का सवाल है गवर्नमेंट को इसकी बडी चिंता है और जल्दी इस पर फैसला हो जाएगा। दो-तीन तारीख को चीफ मिनिस्टर्स की कान्फरैन्स यहां बुला रखी है और इसके बाद सारा फैसला किया जाएगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सदन के इसी सत्र में घोषणा हो जायेगी या नहीं? मैंने यह पूछा था कि हमारा सदन 11 तारीख तक है तो इस 11 तारीख तक इस बात की घोषणा कर सकेंगे या नहीं?

श्री सुलतान सिंह (हरियाणा) : उप-सभापति जी. . .

श्री रबी राय (उड़ीसा) : पोइंट आफ आर्डर। जब स्पेशल मेंशन्स हो रहे हों उस समय डिबेट नहीं होती।

श्री उपसभापति : डिबेट नहीं हो रही है, श्री रबी राय।

श्री सुलतान सिंह : मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूं।

श्री उपसभापति : आपने अपना नाम नहीं दिया था। आपको अपना नाम देना चाहिए था।

श्री सुलतान सिंह : मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ था बीच में ही रबी राय जी बोलने खड़े हो गये थे।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज के जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब हैं, जब 105 रुपए भाव खुले तो इन्होंने सत्याग्रह किया था करनाल में और मैमोरैंडम दिया था कि गेहूं का भाव 150 रुपए होना चाहिये, ट्रेक्टर की कीमत कम होनी चाहिए। आपको याद होगा।

श्री उपसभापति : यह प्रश्न अभी नहीं उठाया जा सकता है। आपको कई मौके मिलेंगे उस समय ये सारी बातें आप कहिये।

REFERENCE TO FUNCTIONING OF INDIAN HIGH COMMISSION IN LONDON

श्री रबी राय (उड़ीसा) : उप-सभापति महोदय आपकी विशेष आज्ञा से मैं एक विशेष महत्व का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस संबंध में आज के स्टेट्समैन अखबार में जो संवाद छपा है, उसको मैं सदन के समाने पढ़ देता हूं——

"London: The Indian High Commission here, very active during the months of the Emergency in propagating New Delhi's policies appears to be still trying to find its feet before taking on the task of enlightening Britons and resident Indians about the new Government's policies and programmes.

The past fortnight has seen far-reaching changes in India, but there has been no Press release or other background data from the mission. This apparent omission can partly be explained by the fact that the public relations counsellor was due to retire (he retired yesterday) and his successor has not yet arrived.

There is wider interest here in the developments in India than in the recent past and an effective public relations exercise should go a long way in giving a clearer idea of the new Government's programmes."

आपकी खिदमत में और सदन की खिदमत में मैं यह महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं कि लन्दन में, युनाईटेड किंगडम में हिन्दुस्तान